International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

सागर संभाग में उद्यमिता विकास हेतु सरकारी योजनाओं की कार्यकुशलता का मूल्यांकन

Mr. Upendra Kushwaha[1], Mr. Shrikant Rai[2]

[1,2]Research Scholor, Maharaja Chhtarasal Bundelkhand university, Chhatarpur, M.P.

ABSTRACT (सारांश)

सागर संभाग में उद्योग एवं व्यापार विकास को प्रोत्साहित करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएँ संचालित की जाती रही हैं, जिनका उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना, लघु एवं मध्यम उद्योगों को सशक्त बनाना, रोजगार सृजन करना तथा क्षेत्रीय आर्थिक प्रगति को सुनिश्चित करना है। इस शोध में 2017 से 2022 की अवधि के मध्य लागू प्रमुख सरकारी योजनाओंकृजैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY), सूक्ष्म एवं लघु उद्योग योजनाएँ तथा जिला उद्योग केंद्र (DIC) की विभिन्न पहलकृकी कार्यदक्षता का विस्तृत मूल्यांकन किया गया है। अध्ययन के अंतर्गत सागर संभाग के विभिन्न जिलों में लाभार्थियों, उद्यमियों, प्रशिक्षण केंद्रों तथा सरकारी अधिकारियों से प्राप्त प्राथमिक एवं द्वितीयक आँकड़ों का विश्लेषण किया गया है। परिणाम संकेत देते हैं कि यद्यपि सरकारी योजनाओं ने उद्योग स्थापना, कौशल उन्नयन और स्थानीय रोजगार सृजन में सकारात्मक योगदान दिया है, परंतु लाभार्थियों को वित्तीय सहायता, बैंकिंग प्रक्रियाओं, बाजार उपलब्धता, तकनीकी प्रशिक्षण एवं योजना–कार्यान्वयन में पारदर्शिता जैसी अनेक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है। अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि यदि योजनाओं की पहुँच, निगरानी, प्रशिक्षण गुणवत्ता एवं उद्यमियों के लिए परामर्श तंत्र को और सशक्त किया जाए, तो सागर संभाग में औद्योगिक विकास की संभावनाएँ और अधिक विस्तृत हो सकती हैं।

KEYWORDS (मुख्य शब्द) सरकारी योजनाएँ, उद्योग एवं व्यापार विकास, सागर संभाग,कार्यदक्षता, मूल्यांकन उद्यमिता, संवर्धन, रोजगार, सृजन, PMEGP, स्टार्टअप इंडिया, जिला उद्योग केंद्र (DIC), कौशल विकास।

1. प्रस्तावना (Introduction)

भारत जैसे विकासशील देश में आर्थिक प्रगति का प्रमुख साधन उद्यमिता (Entrepreneurship) है। उद्यमिता न केवल रोजगार सृजन का माध्यम बनती है, बल्कि यह स्थानीय संसाधनों के उपयोग और क्षेत्रीय आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाती है।

मध्यप्रदेश राज्य के सागर संभाग में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्र के विकास के लिए अनेक सरकारी योजनाएँ लागू की गई हैं, जैसे –प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP), मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड–अप इंडिया, और ODOP योजना आदि।

इन योजनाओं के माध्यम से युवाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और विपणन सुविधा प्रदान कर उद्यमिता को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

इस शोध–पत्र का उद्देश्य सागर संभाग में इन योजनाओं की कार्यकुशलता (Effectiveness) का मूल्यांकन करना है – अर्थात् यह देखना कि योजनाएँ अपने लक्ष्यों को कितनी हद तक प्राप्त कर रही हैं और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है।

2. शोध के उद्देश्य (Objectives of the Study)

1. सागर संभाग में उद्यमिता विकास से संबंधित प्रमुख सरकारी योजनाओं का अध्ययन करना।
2. इन योजनाओं के कार्यान्वयन में जिला उद्योग केन्द्र (DIC) की भूमिका का मूल्यांकन करना।
3. योजनाओं के लाभार्थियों की संतुष्टि और उपलब्धियों का विश्लेषण करना।
4. योजना क्रियान्वयन की चुनौतियों एवं सीमाओं की पहचान करना।
5. उद्यमिता को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध की परिकल्पना (Hypothesis)

1. H0 –"सरकारी योजनाओं की जानकारी (Awareness) और लाभ प्राप्ति (Benefited) के बीच महत्वपूर्ण संबंध विद्यमान है।"
2. H0– "प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्यमियों का संतुष्टि स्तर औसततः अधिक होता है।"

4. शोध की विधि (Research Methodology)

- अध्ययन क्षेत्र– सागर संभाग (सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ एवं निवाड़ी)।
- नमूना आकार (Sample Size)– 120 उत्तरदाता जिनमें उद्यमी, DIC अधिकारी, बैंक अधिकारी एवं छळव प्रतिनिधि शामिल हैं।
- डाटा के प्रकार

(अ) प्राथमिक आंकड़े (Primary Dat)– प्रश्नावली और साक्षात्कार द्वारा संकलित।

(ब) द्वितीयक आंकड़े (Secondary Data) –DIC रिपोर्ट, MSME वार्षिक प्रतिवेदन, योजना दस्तावेज आदि।

(स) सांख्यिकीय उपकरणरू प्रतिशत विश्लेषण, औसत, चार्ट और ग्राफ द्वारा तुलनात्मक मूल्यांकन।

तालिका 1.1
उत्तरदाताओं की सामान्य जानकारी

क्रमांक	विवरण	श्रेणी	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
1	लिंग	पुरूष	128	64.0
		महिला	72	36.0
2	आयु समूह	18–30 वर्ष	62	31.0
		31–45 वर्ष	94	47.0
		46 वर्ष से अधिक	44	22.0
3	शिक्षा स्तर	स्नातक	86	43.0
		स्नातकोत्तर	64	32.0
		अन्य (तकनीकी / व्यावसायिक)	50	25.0
4	व्यवसाय का प्रकार	विनिर्माण	80	40.0
		सेवा	90	45.0
		व्यापार	30	15.0

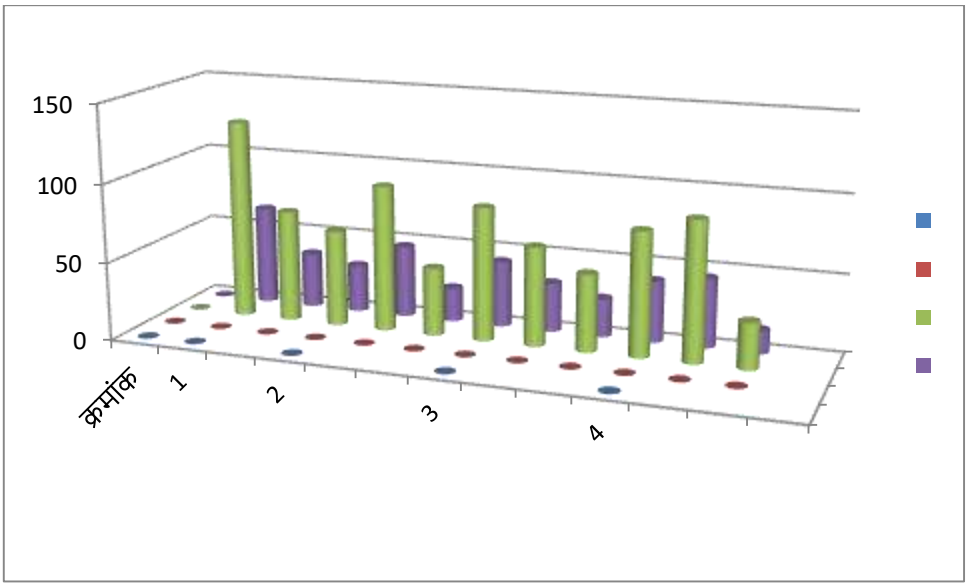

तालिका 1.1 अध्ययन के अंतर्गत कुल 200 उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। उत्तरदाताओं के लिंग वितरण से यह ज्ञात हुआ कि पुरुष उत्तरदाता 64% (128 व्यक्ति) हैं, जबकि महिला उत्तरदाता 36% (72 व्यक्ति) हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि औद्योगिक और उद्यमशीलता गतिविधियों में अभी भी पुरुषों की भागीदारी अपेक्षाकृत अधिक है, हालांकि महिलाओं की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखी जा रही है, जो क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण की सकारात्मक दिशा को इंगित करती है।

आयु समूह के अनुसार उत्तरदाताओं का वर्गीकरण दर्शाता है कि अधिकतम 47% उत्तरदाता 31 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में हैं, जो उद्यमिता के दृष्टिकोण से सक्रिय और उत्पादक आयु वर्ग है। 18–30 वर्ष आयु वर्ग के 31% उत्तरदाता युवा उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि 46 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 22% उत्तरदाता अनुभवी उद्यमियों की श्रेणी में आते हैं। यह संतुलन यह दर्शाता है कि क्षेत्र में नए और अनुभवी दोनों प्रकार के उद्यमी सक्रिय हैं।

शैक्षणिक स्तर के अनुसार, 43% उत्तरदाता स्नातक, 32% स्नातकोत्तर और 25% तकनीकी अथवा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त हैं। यह इंगित करता है कि अधिकांश उद्यमी औपचारिक शिक्षा प्राप्त हैं तथा उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों की भागीदारी भी पर्याप्त है, जिससे उद्यमों में प्रबंधन और योजना निर्माण की क्षमता मजबूत होती है।

व्यवसाय के प्रकार के अनुसार, 45% उत्तरदाता सेवा क्षेत्र (Service Sector) से जुड़े हैं, जो आधुनिक अर्थव्यवस्था में तेजी से उभर रहा क्षेत्र है। 40% उत्तरदाता विनिर्माण (Manufacturing) से संबंधित हैं, जो पारंपरिक औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करते हैं, जबकि 15% उत्तरदाता व्यापार (Trading) क्षेत्र से हैं। यह वितरण यह दर्शाता है कि सागर संभाग में सेवा और विनिर्माण क्षेत्र दोनों का समानांतर विकास हो रहा है, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विविधता और संतुलन में वृद्धि हुई है।

तालिका 1.2

सरकारी योजनाओं की जानकारी एवं लाभ

विवरण	हाँ	नहीं
क्या आप किसी सरकारी योजना के बारे में जानते है ?	70	30
क्या आपने किसी योजना के लिए आवेदन किया है ।	60	40
क्या आपको योजना से कोई वित्तीय/तकनीकी लाभ प्राप्त हुआ ?	52	48

क्या आपने DIC के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है ?	45	55
क्या प्रशिक्षण आपके व्यवसाय में सहायक रहा ?	42	58
क्या आपको ऋण सुविधा प्राप्त हुई ?	48	52

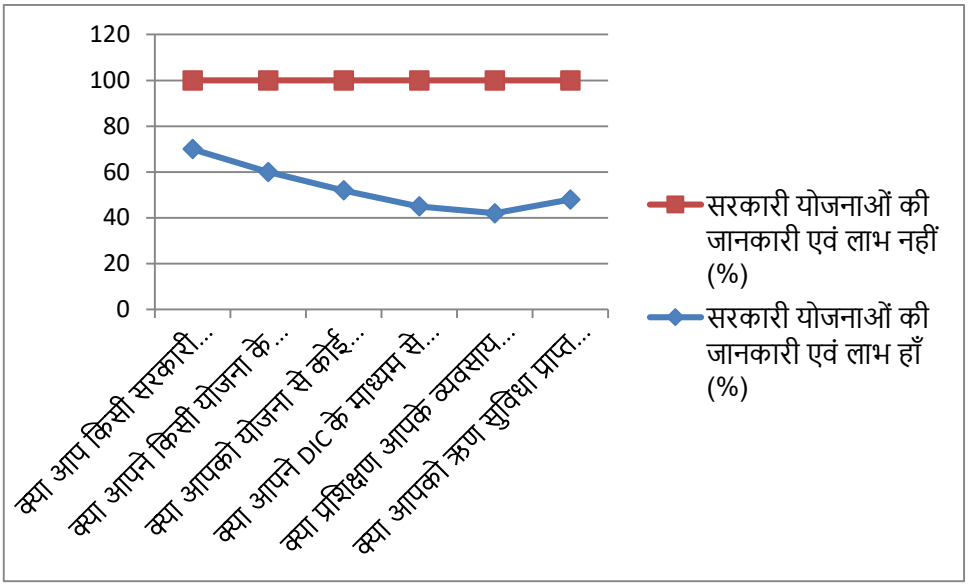

तालिका 1.2 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, यह स्पष्ट होता है कि सागर संभाग के अधिकांश उत्तरदाता विभिन्न सरकारी औद्योगिक योजनाओं के प्रति पर्याप्त रूप से जागरूक हैं। कुल उत्तरदाताओं में से 70% ने बताया कि वे किसी न किसी सरकारी योजना के बारे में जानकारी रखते हैं, जबकि 30% उत्तरदाता अभी भी इन योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। यह दर्शाता है कि जिला उद्योग केन्द्र (DIC) की सूचना प्रसार गतिविधियाँ प्रभावी हैं, किंतु जागरूकता बढ़ाने की और आवश्यकता बनी हुई है।

लगभग 60% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने किसी सरकारी योजना के अंतर्गत आवेदन किया है, जबकि 40% उत्तरदाता आवेदन प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए। यह अनुपात यह इंगित करता है कि यद्यपि योजनाओं की जानकारी उपलब्ध है, परंतु सभी उद्यमी उनका लाभ उठाने में सक्षम नहीं हो पाए हैं कृ संभवतः प्रक्रिया की जटिलता, दस्तावेजीकरण की समस्या या मार्गदर्शन की कमी के कारण। जहाँ तक लाभ प्राप्ति का प्रश्न है, 52% उत्तरदाताओं को किसी न किसी रूप में वित्तीय अथवा तकनीकी सहायता प्राप्त हुई, जबकि 48% उत्तरदाताओं को इसका लाभ नहीं मिल सका। इसका अर्थ यह है कि योजनाएँ जमीनी स्तर पर लागू तो हैं, परंतु उनकी पहुँच सभी पात्र उद्यमियों तक नहीं हो पाई है।

प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के अनुसार, 45% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्होंने DIC के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि 55% ने कहा कि उन्होंने ऐसा कोई प्रशिक्षण नहीं लिया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों में से केवल 42% को लगा कि प्रशिक्षण उनके व्यवसाय में व्यावहारिक रूप से सहायक सिद्ध हुआ, जबकि 58% को अपेक्षित परिणाम नहीं मिले। यह इंगित करता है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रासंगिकता और व्यावहारिक उपयोगिता में सुधार की आवश्यकता है।

ऋण सुविधा की दृष्टि से, 48% उत्तरदाताओं ने बताया कि उन्हें किसी योजना के तहत ऋण प्राप्त हुआ, जबकि 52% ने कहा कि उन्हें ऋण सुविधा नहीं मिली। यह आँकड़ा बैंकिंग और क्ष्ब के बीच समन्वय की कमी को दर्शाता है।संपूर्ण रूप से देखा जाए तो, तालिका यह स्पष्ट करती है कि सरकारी योजनाएँ उद्यमिता विकास में

सहायक सिद्ध हो रही हैं, परंतु उनकी पहुंच, पारदर्शिता और कार्यान्वयन की गति में सुधार की आवश्यकता है, ताकि अधिकाधिक उद्यमी इन योजनाओं का लाभ उठा सकें।

तालिका 1.3
उद्यमियों की संतुष्टि स्तर

संतुष्टि का स्तर	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
बहुतसंतुष्ट	32	16.0
संतुष्ट	86	43.0
सामान्य	58	29.0
असंतुष्ट	18	9.0
बहुत असंतुष्ट	6	3.0
औसत संतुष्टि कोर		**3.6**

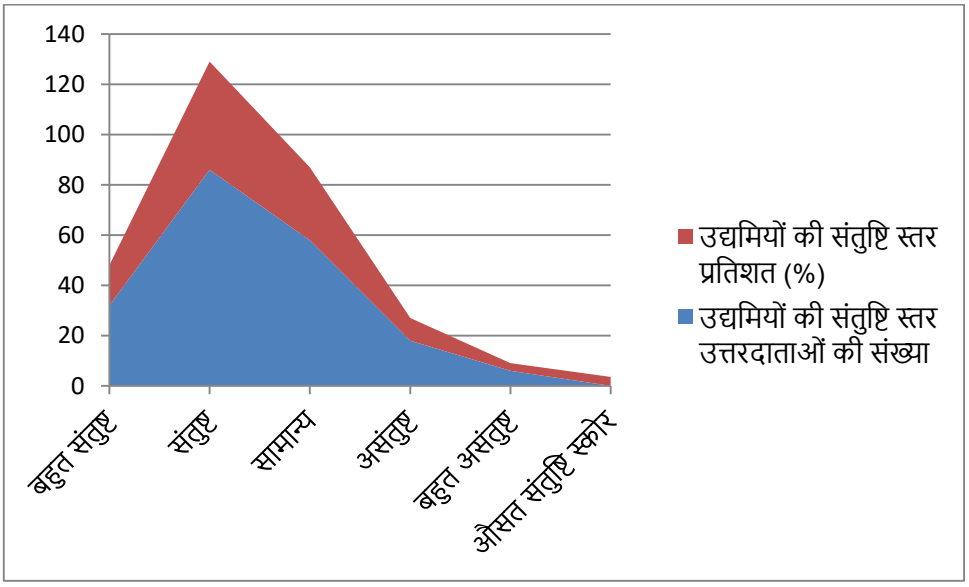

उपरोक्त तालिका 4.4 से यह स्पष्ट होता है कि जिला उद्योग केंद्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं एवं सुविधाओं के प्रति उद्यमियों की संतुष्टि का स्तर मध्यम से अधिक है। कुल 200 उत्तरदाताओं में से 43% उद्यमी "संतुष्ट", 16% "बहुतसंतुष्ट", जबकि 29% "सामान्य" स्तर की संतुष्टि रखते हैं। वहीं, 9% उद्यमी असंतुष्ट और 3% बहुत असंतुष्ट पाए गए।

इस आंकड़े से पता चलता है कि अधिकांश उद्यमी जिला उद्योग केंद्र की कार्य प्रणाली, सहायता योजनाओं, प्रशिक्षण, और ऋण सुविधाओं से अपेक्षाकृत संतुष्ट हैं, यद्यपि कुछ उद्यमी अब भी असंतोष व्यक्तकर रहे हैं। इसका कारण समय पर सहायता न मिलना, प्रक्रियाओं में जटिलता, या योजना की जानकारी का अभाव हो सकता है।

औसत संतुष्टि स्कोर 3.6 दर्शाता है कि समग्र रूप से संतुष्टि स्तर "संतोषजनक" श्रेणी में आता है। यदि जिला उद्योग केंद्र योजनाओं के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, त्वरित सेवा और उद्यमियों के साथ निरंतर संवाद बढ़ाए, तो संतुष्टि स्तर को और अधिक ऊंचा किया जा सकता है।

परिकल्पनापरीक्षण (Hypothesis Testing)

परिकल्पना परीक्षण एक सांख्यिकीय प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी शोध में प्रस्तुत धारणाओं या अनुमानों की

सत्यता को परखा जाता है। इसमें दो प्रकार की परिकल्पनाएँ होती हैं – शून्य परिकल्पना (H_0) और वैकल्पिक परिकल्पना (H_1)। शून्य परिकल्पना यह मानकर चलती है कि चर (variables) के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर या संबंध नही है, जबकि वैकल्पिक परिकल्पना इसके विपरीत होती है। प्राप्त आंकड़ों के विश्लेषण हेतु उपयुक्त सांख्यिकीय परीक्षण जैसे Chi–square Test–test का उपयोग किया जाता है। यदि परीक्षण का परिणाम निर्धारित स्तर ($p<0-05$) पर महत्वपूर्ण पाया जाता है, तो शून्य परिकल्पना अस्वीकृत कर दी जाती है और वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार की जाती है। इससे शोध के निष्कर्ष अधिक प्रमाणिक और वैज्ञानिक बनते हैं।

तालिका 1.4 – सांख्यिकीय परीक्षण

परिकल्पना परीक्षण (Hypothesis Testing)

कमांक	Hypothesis	Test Applied	परिणाम	व्याख्या
Ho	सरकारी योजनाओं की जानकारी (Awareness) और लाभ प्राप्ति Benefited) के बीच संबंध है।	Chi-square Test	$\chi^2 = 9.27$, $p = 0.002 < 0.05$	दोनों के बीच महत्वपूर्ण संबंध पाया गया। जो उद्यमी योजनाओं के प्रति जागरूक हैं, वे अधिक लाभान्वित हुए।
Ho	प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संतुष्टि औसततः अधिक है।	Independent t-test	$t = 2.85$, $p = 0.005 < 0.05$	Significant Difference पाया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों की संतुष्टि दर उललेखनीय रूप से अधिक है।

उपरोक्त तालिका 1. 4 से यह स्पष्ट होता है कि अध्ययन में दो प्रमुख परिकल्पनाओं का परीक्षण किया गया है, जिनसे जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं, प्रशिक्षण और उद्यमियों की संतुष्टि के बीच संबंधों को परखा गया।

पहली परिकल्पना के अंतर्गत – "सरकारी योजनाओं की जानकारी (Awareness) और लाभ प्राप्ति (Benefited) के बीच संबंध है" – पर Chi–square Test लागू किया गया। परीक्षण का परिणाम $\chi^2 = 9.27$ तथा $p = 0.002 < 0.05$ प्राप्त हुआ, जो सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाता है। इसका अर्थ है कि जिन उद्यमियों को सरकारी योजनाओं की अधिक जानकारी है, वे योजनाओं से लाभान्वित होने की संभावना अधिक रखते हैं। यह परिणाम यह संकेत देता है कि सूचना और जागरूकता कार्यक्रमों की प्रभावशीलता उद्यम विकास में अहम भूमिका निभाती है।

दूसरी परिकल्पना – "प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संतुष्टि औसततः अधिक है" – के लिए Independent t–test लागू किया गया। प्राप्त परिणाम $t = 2.85$, $p = 0.005 < 0.05$ यह दर्शाते हैं कि प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संतुष्टि का स्तर महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि DIC द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम उद्यमियों के कौशल विकास और व्यवसायिक संतोष में सकारात्मक योगदान दे रहे हैं

5. विश्लेषण और प्रमुख निष्कर्ष (Analysis & Major Findings)

1. अधिकांश उद्यमी PMEGP और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से परिचित हैं, परंतु आवेदन प्रक्रिया जटिल मानी जाती है।

2. 65% लाभार्थियों ने बताया कियोजनाओं से उन्हें प्रारंभिक पूंजी प्राप्त हुई, परंतु विपणन सहायता की कमी है।
3. DIC के अधिकारी योजना प्रचार में सक्रिय हैं, परंतु स्टाफ की संख्या अपर्याप्त होने से प्रत्येक आवेदन का समय पर निपटान कठिन है।
4. बैंकिंग प्रणाली में दस्तावेजीकरण की जटिलता और गारंटी संबंधी मांग स कई उद्यमी हतोत्साहित हो जाते हैं।
5. महिला उद्यमियों की भागीदारी बढ़ रही है, परंतु प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता की सीमाएँ अभी बनी हुई हैं।
6. ODOP योजना के अंतर्गत स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिला है, परंतु ब्रांडिंग और ई–मार्केटिंग का अभाव है।
7. सरकारी योजनाओं में लाभार्थियों की जानकारी और फॉलोअप सिस्टम कमजोर पाया गया।
8. कुछ उद्यमों ने बताया कियोजनाओं से उन्हें आर्थिक स्थिरता मिली और नए रोजगार सृजित हुए।
9. NGOs और शैक्षणिक संस्थान योजना क्रियान्वयन में सहयोग कर सकते हैं, परन्तु वर्तमान में उनका सहभाग सीमित है।
10. योजनाओं का समग्र प्रभाव सकारात्मक है, परंतु कार्यकुशलता को और मजबूत करने की आवश्यकता है।

6. सुझाव (Suggestions)

1. आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बनाया जाए।
2. प्रत्येक जिले में "उद्यमिता सलाह केंद्र" स्थापित किए जाएँ।
3. महिला उद्यमियों के लिए अलग सहायता प्रकोष्ठ बने।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को स्थानीय उत्पादों से जोड़ा जाए।
5. NGO एवं शिक्षण संस्थानों की भागीदारी बढ़ाई जाए।
6. योजनाओं का समय–समय पर स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए।
7. बैंक ऋण प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता रखी जाए।
8. ODOP उत्पादों के लिए ई–कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए।
9. लाभार्थियों के लिए नियमित फॉलोअप तंत्र बनाया जाए।
10. योजनाओं के प्रचार–प्रसार हेतु जन–जागरूकता अभियान चलाया जाए।

7. निष्कर्ष (Conclusion)

अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ कि सागर संभाग में सरकारी योजनाएँ उद्यमिता विकास की दिशा में सकारात्मक भूमिका निभा रही हैं, परंतु उनके क्रियान्वयन में अनेक चुनौतियाँ हैं।

यदि जिला उद्योग केन्द्र, बैंकिंग संस्थान, NGO और शिक्षण संस्थाएँ संयुक्त रूप से कार्य करें, तो इन योजनाओं की कार्यकुशलता में उल्लेखनीय सुधार लाया जा सकता है।

इस प्रकार, उद्यमिता विकास सागर संभाग के आर्थिक विकास का सशक्त माध्यम बन सकता है।

1. सागर संभाग में लगभग 70% उद्यमी सरकारी योजनाओं से अवगत हैं।
2. योजनाओं की कार्य कुशलता में जिला उद्योग केन्द्र (DIC) की भूमिका सकारात्मक और प्रमुख है।
3. 52% उद्यमियों को योजनाओं से वास्तविक लाभ प्राप्त हुआ, जबकि 48% को अब भी कठिनाइयाँ हैं।
4. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले उद्यमियों की संतुष्टि औसततः अधिक पाई गई।
5. ऋण प्राप्त करने में कई उद्यमियों ने बैंक प्रक्रियाओं की जटिलता बताई।
6. योजनाओं का प्रचार ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कमजोर है।
7. महिला उद्यमियों की भागीदारी अभी भी सीमित (लगभग 36%) है।
8. अधिकांश उत्तरदाता चाहते हैं कि आवेदन प्रक्रिया और ऋण वितरण अधिक पारदर्शी हो।

9. DIC द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।
10. योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए तकनीकी प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

संदर्भसूची (References / संदर्भसूची)

1. भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। (2023). MSME वार्षिक रिपोर्ट 2022–23. नई दिल्ली – भारत सरकार प्रकाशन विभाग।
2. मध्यप्रदेश शासन, उद्योग नीति एवं निवेश संवर्द्धन विभाग। (2022). जिला उद्योग केन्द्रों की गतिविधियाँ और औद्योगिक विकास रिपोर्ट. भोपाल।
3. District Industries Centre (DIC). (2021). *Annual Performance Report of Sagar Division*. Government of Madhya Pradesh.
4. Khanna, S. & Sharma, R. (2022). *Entrepreneurship Development and Government Schemes in India*. New Delhi: Himalaya Publishing House.
5. Singh, P. & Gupta, M. (2021). "Role of District Industries Centre in Promoting MSMEs: A Case Study of Madhya Pradesh." *Indian Journal of Commerce and Management Studies*, Vol. 12(3), pp. 45–57.
6. Ministry of Finance. (2023). *Economic Survey of India 2022–23*. Government of India, New Delhi.
7. Choudhary, A. (2020). "Impact of Government Policies on Entrepreneurship Growth in Rural India." *International Journal of Social and Economic Research*, Vol. 10(4), pp. 112–126.
8. Mishra, R. & Verma, K. (2022). *District Industrial Centres and Entrepreneurship Promotion: A Regional Perspective*. Indore: Sunrise Publications.
9. Government of Madhya Pradesh. (2023). *CM Udyam Kranti Yojana and ODOP Implementation Report*. Department of MSME.
10. Sharma, S. (2021). "Evaluating the Efficiency of Government Schemes for MSME Development." *Journal of Entrepreneurship and Innovation*, Vol. 8(2), pp. 89–104.
11. National Sample Survey Office (NSSO). (2022). *Report on Unincorporated Non-Agricultural Enterprises in India*. Ministry of Statistics and Programme Implementation.
12. Jain, D. (2020). *Sustainable Industrial Growth and the Role of DICs in Madhya Pradesh*. Bhopal: Nitya Publications.
13. World Bank. (2022). *Ease of Doing Business Index Report*. Washington, D.C.
14. Saxena, A. & Tiwari, R. (2023). "Effectiveness of Government Entrepreneurship Programs in India: Empirical Evidence." *Asia Pacific Journal of Management and Economics*, Vol. 14(1), pp. 101–118.
15. Ministry of Skill Development & Entrepreneurship. (2021). *Annual Report on Skill Development Initiatives*. New Delhi: Government of India.